ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-410-415, YEAR-2014

खालिस्तान आंदोलन : पुरानी समस्या के नए आयाम (एक मूल्यांकन)

❑ प्रो.(डॉ) सतीश चन्द्र पाण्डेय

सार– *खालिस्तान विमर्श अलग–अलग रूपों और सघनता के साथ देश के समक्ष प्रस्तुत होता रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते। भारत को खालिस्तान समर्थकों के साथ–साथ खालिस्तान के वैचारिक अधिष्ठान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी होगी। आज हमारे देश के समक्ष एक अपरंपरागत सुरक्षा खतरे के रूप में उत्पन्न खालिस्तान समस्या का इतिहास करीब 150 वर्ष पुराना है। अंग्रेज भारत में 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए "बांटो और राज करो" की विभाजनकारी नीति अपनाई जिसके लिए उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियां चिन्हित कर बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर पर काम किया। उस समय अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू–सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था क्योंकि सिख पंथ के जन्म से ही प्रत्येक हिंदू सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा था तो गुरु परंपरा से उपजा प्रत्येक सिख स्वयं को धर्म और देश का रक्षक मानता है। यूं तो अधिकांश हिंदू और सिखों पर इसका असर नहीं पड़ा परंतु सिख पंथ का एक वर्ग इसके प्रभाव में आ गया इसका बहुत विस्तृत और काला इतिहास है। इस विमर्श को सिख पंथ का एक बहुत छोटा मगर मुखर वर्ग आगे बढ़ा रहा है। जो भारत विरोधी शक्तियों के समर्थन से लगातार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता रहता है।*

खालिस्तान एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खालसा की भूमि, खालसा अरबी भाषा का शब्द है। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह ने साल 1699 में की थी। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध लेकिन समय बीतने के साथ–साथ इस विचार के उद्देश्य परिवर्तित हो गए, जिसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, इसे समझने के लिए हमें आंदोलन से जुड़े इतिहास को भली भांति समझने की आवश्यकता है तभी हम इस आंदोलन के वास्तविक अर्थ और इसके प्रभाव को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए हमें आज से 103 वर्ष पहले की उसे घटना को ध्यान में रखना होगा जब 1920 ई. में राष्ट्रपिता गांधीजी के असहयोग आंदोलन के जरिए देश में अंग्रेजों के विरोध की एक लहर से दौड़ रही थी। ठीक इसी समय पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई । इसका प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सिखों के प्रमुख गुरुद्वारों जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर, अकाल तख्त, बाबा अताई और तरनतारन सहित कई प्रमुख गुरुद्वारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इनका इस्तेमाल अंग्रेजी सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रही थी । क्योंकि सिख आबादी के मध्य गुरुद्वारों का खास महत्व था और बाकी बच्चे लगभग 260 गुरुद्वारों को महंतों के हाथों में रहने दिया गया। भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के कारण सिखों के मन में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार इन संतों को समर्थन कर रही थी। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का उद्देश्य गुरुद्वारों को ऐसे ही भ्रष्टाचारी महंतों से मुक्त कराना था। यह आंदोलन लगभग 5 सालों तक चला और सन 1925 आते–आते अंग्रेजों ने संघर्ष कर रहे सिखों

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

की ज्यादातर बातें मान ली थी जिसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया,परंतु आंदोलन की खास बात यह रही कि इस आंदोलन के दौरान सिख समुदाय कई वर्गों में विभाजित हो गया जिसमें से एक वर्ग ने इस आंदोलन को सिख सांप्रदायिकता का मंच बना दिया। ऐसा करने वाले लोगों ने धीरे–धीरे सिखों को हिंदुओं और मुसलमान से अलग दिखना शुरू किया। हिंदुओं के लिए सिखों के मन में अलगाव की भावना के पीछे दो प्रमुख वजह थी पहली यह कि भारतीय समाज में हिंदू समुदाय ज्यादा प्रभावशाली था और दूसरी वजह यह थी कि सरकारी नौकरियों और राजनीति में सिखों की स्थिति कमजोर थी और इन्हीं सब स्थितियों की वजह से सिखों के मन में धीरे–धीरे मनभेद शुरू हो गया और यहीं से अलग सिख देश की मांग ने जन्म लिया और इसके लिए सिखिस्तान शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसी बीच वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी और अंग्रेजों से भारत को आजाद करने का संकल्प लिया लेकिन इस दौरान मास्टर ताराचंद्र के नेतृत्व में सिखों के एक समूह ने यह मांग रखी कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सीट आरक्षित की जाती है तो इस आधार पर सिख अल्पसंख्यकों के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। मास्टर ताराचंद्र उसी शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के संस्थापक सदस्यों में से थे जिसका गठन गुरुद्वारों को मुक्त करने के लिए किया गया था। मास्टर ताराचंद्र को इस बात की शंका थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में आजाद भारत में राजनीतिक हिस्सेदारी में सिखों की भूमिका बहुत सीमित रह जाएगी क्योंकि सिखों की आबादी उस समय भी हिंदू और मुसलमानों के मुकाबले काफी कम थी। इन्हीं वजहों के लिए बाद में सिखों के लिए अलग देश की मांग उठी और ऐसा माना जाता है कि खालिस्तान शब्द का विचार यहीं से अस्तित्व में आया हालांकि तब खालिस्तान की जगह सिक्खिस्तान शब्द का ही इस्तेमाल होता था। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली परंतु आजाद भारत में पंजाब राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। इस बंटवारे ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों की अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। परंतु साल 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इसी को आधार बनाकर अकाली दल ने धर्म के आधार को छोड़कर भाषा को आधार बनाते हुए पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। संत फतह सिंह ने पंजाब सूबा नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका मकसद था पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए गलत राज्य की स्थापना करना। 19 साल तक पूरे पंजाब में इसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस आंदोलन के दौरान राज्य में जगह–जगह पर हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी और आखिरकार सन 1966 में भारत सरकार ने पंजाब राज्य को तीन हिस्सों में विभाजित करने का फैसला लिया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था जिसे दोनों प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पहाड़ी हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। सरकार कैसे बड़े फैसले की बावजूद कुछ लोग खुश नहीं थे कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो कुछ लोग साझा राजधानी के विचारों से खफा थे। पंजाब के बंटवारे के बाद से खालिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आया यह वह दौर था जब खालिस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जिन्होंने आनंदपुर प्रस्ताव पारित किया। आनंदपुर प्रस्ताव को सरदार कपूर सिंह ने अंग्रेजी भाषा में तैयार किया था और सबसे पहले संत फतह सिंह को मौखिक रूप से समझाया था जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इस प्रस्ताव की तीन प्रमुख मांगी थी पहली मांग यह थी कि पंजाब की नदियों सतलुज और रावी के पानी का बंटवारा फिर से हो, दूसरी मांग थी कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब

को सौंप दिया जाए और तीसरी मांग यह थी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उन जिलों को जिसमें सिखों की आबादी अधिक है उनको पंजाब में शामिल किया जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों के लिए ज्यादा स्वायत्त पंजाब राज्य की मांग के लिए एक अलग संविधान की भी मांग रखी गई थी। 1980 तक सिखों के मध्य इस प्रस्ताव के लिए समर्थन बढ़ता गया लेकिन इस बीच खालिस्तान आंदोलन को राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकी जिसकी वजह से पंजाब में अलगाववादी विचारधारा मजबूत होने लगी और सिखों के लिए खालिस्तान नामक एक अलग देश की स्थापना की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इस समय तक आते–आते पंजाब राज्य में चरमपंथ अपने शीर्ष पर था और जरनैल सिंह भिंडरवाला इसका पोस्टर ब्वॉय बन गया। जो दमदमी टकसाल का प्रमुख था। साल 1980 से 1984 के बीच पूरे पंजाब में हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएँ की गई तथा हिंदुओं और सिखों के मध्य टकराव पैदा करने की कोशिश की गई। भिंडरवाले ने शुरुआत में निरंकारियों और खालिस्तान का विरोध करने वालों को अपना निशाना बनाया और इसके बाद पत्रकार, नेता, पुलिस और हिंदू समुदाय के लोग भी उसके निशाने पर आ गए। वर्ष 1982 में भिंडरवाले ने अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से धर्म युद्ध मोर्चा नामक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी जड़े मजबूत कर ली तथा जून 1984 तक हालात इतने बिगड़ गए कि खालिस्तानी अलगाववादियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी को 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, इस ऑपरेशन में 83 जवान शहीद हुए और 493 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे जिनमें जरनैल सिंह भिंडरवाला भी था। इसका नतीजा यह हुआ कि इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगों ने पंजाब के हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया। पूरा राज्य खालिस्तान समर्थक चरमपंथ की आग में जलने लगा जिसे रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे कई बड़े और छोटे ऑपरेशन चलाए। इस दौरान खालिस्तान आंदोलन से संबंधित चरमपंथी समूहों द्वारा लगभग 7126 निर्दोष लोगों और 1075 पुलिस वालो की हत्या कर दी गई। पूरे एक दशक तक चले इस हिंसक मंजर से जनता भी घबरा गई थी परंतु सरकार और पुलिस की कार्यवाही ने धीरे–धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को काफी हद तक बुझा दिया था लेकिन इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थकों के मन में जल रही थी जिसे समय–समय पर बाहरी शक्तियों द्वारा हवा दिया जाता रहा। दरअसल खालिस्तान आंदोलन न सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ है बल्कि इसके तार दूर–दूर तक फैले हुए हैं। खालिस्तान समर्थक भारत से बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे देशों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। भारत से बाहर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा योगदान जगजीत सिंह चौहान कर रहा है जो पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे थे। सन 1969 में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जगजीत सिंह भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए और उन्होंने वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की तथा साल 1971 में अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान देश की स्थापना के लिए एक इश्तिहार प्रकाशित कराया और इसके बाद लंदन में 1971 में ही खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की जहां पर उसने प्रस्तावित देश का डाक टिकट भी जारी किया परंतु ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान की मुहिम को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी बीच 1971 में हुए युद्ध में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान ने ब्लीड इंडिया पॉलिसी के तहत खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की और जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया जहां उसे पंजाब के सिख नेता के रूप में प्रसारित किया गया। हालांकि इन सब कोशिशें के बावजूद भी जगजीत सिंह चौहान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। भारत के

बाहर बैठे ये खालिस्तान समर्थक सरगना न सिर्फ खालिस्तान के लिए आंदोलन चलाते हैं बल्कि हर जगह भारत विरोधी गतिविधियां भी चलाते हैं मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजर 1994 से पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख बाघवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जरनैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड लाहौर में रहकर ही कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों को एकजुट करने का काम करता था। रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इंडिया हेड है वह भी लाहौर में रहकर ही पंजाब में खालिस्तान समेत कई आतंकवादी गतिविधियां चल रहा है।

1993 में खालिस्तानी आतंकवाद की व्यापक हार के बाद से इस आंदोलन से जुड़े संगठनों का यह प्रयासों का लगातार इतिहास रहा है कि विभिन्न हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास करते रहें, जिसका चक्र दो से चार साल का है। पंजाब पुलिस के सूत्रों से पता चलता है कि 1995–2005 के दौरान पंजाब में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन, बाजार, सिनेमा हॉल आदि जैसे आसान लक्ष्यों पर बम हमलों में मारे गए हैं। उच्च तीव्रता वाले आतंकवाद के वतन के बाद सबसे खराब साल 1997 था जब 14 मार्च से 10 जुलाई के बीच बम धमाकों की घटनाओं में 56 लागरिक मारे गए थे। वर्ष 2000 में कम से कम 18 नागरिक मारे गए, और 2002 में पाँच। जबकि इसके बाद तीन वर्षों में पंजाब में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है (वर्ष 2005 में एकमात्र मौत दिल्ली में सिनेमा हॉल धमाकों में हुई थी), लेकिन गिरतारियों और हथियारों तथा विस्फोटकों की जब्ती का सिलसिला जारी रहा है, जो आतंक की पुनर्जीवित करने के लिए निस्तर प्रयासों का संकेत देता है, जिसे हर बार जनता के समर्थन की पूर्ण अनुपस्थिति और पंजाब पुलिस की अत्यधिक उन्नत खुफिया क्षमताओं के कारण दवा दिया गया। इस अवधि में राज्य में आतंकवादी कोशिकाओं में 1,000 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. साथ ही बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार जिनमें असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड लांचर, साथ ही अन्य उपकरण भी शामिल है, और कम से कम 30 पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल को निष्क्रिय किया गया है।10 इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पंजाब राज्य में जो खालिस्तान आंदोलन अलग पंजाब राज्य की स्थापना की कोशिश के रूप में शुरू हुआ था वह अब अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुका है और अब इस इस आंदोलन ने एक नया आयाम प्राप्त कर लिया है जिसका उद्देश्य भारत विरोधी गतिविधियों के द्वारा भारत को बदनाम करना तथा भारत में अशांति फैलाने और अपने .तियां द्वारा भारत के बाहर भी भारतीय मूल्यों एवं भारतीय चिन्हों का अपमान करना तथा भारत के लोगों को हिंसात्मक घटनाओं का लक्ष्य बनाना शामिल है। इस आंदोलन से जुड़े आतंकवादी संगठन और आतंकवादी नेता पूरी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइ एस आई के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और उसी के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। इस आंदोलन से उपजे प्रमुख आतंकवादी संगठन निम्नलिखित हैंरू

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनलरू बब्बर खालसा इंटरनेशन (BKI) की उत्पत्ति 1920 के बब्बर अकाली आंदोलन से जुड़ी है। हालाँकि, इसका नवीनतम हिंसक अवतार 13 अप्रैल, 1978 को निरंकारियों और अखंड कीर्तनी जत्था के कार्यकर्ताओं के बीच सांप्रदायिक संघर्ष के बाद बना था। संघर्ष के परिणामस्वरूप अखंड कीर्तनी जत्था प्रमुख फौजा सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद 1979–80 के दौरान, सुखदेव सिंह बब्बर और तलविंदर सिंह परमार के नेतृत्व में अखंड कीर्तनी जत्था के सदस्यों ने ठज्ञप् का गठन किया। BKI का अस्तित्व पहली बार उन पर्चों में सामने आया, जो 1980 में निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख की हत्या के बाद बांटे गए थे। BKI के कम से कम दो ज्ञात गुट हैं। पहला अलग गुट 1992 में

बना, जब BKI के सह–संस्थापक तलविंदर सिंह परमार मुख्य निकाय से अलग हो गए और बब्बर खालसा परमार का गठन किया। इस गुट की मौजूदगी मुख्य रूप से यूरोप (यूके, जर्मनी, बेल्जियम और स्विटजरलैंड) के साथ–साथ उत्तरी अमेरिका में भी है।11

2.खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ)रू खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) का गठन 1986 के अंत में अरुर सिंह ने अपने 'प्रमुख' के रूप में किया था। पंथिक समिति से निकाले जाने के बाद उन्होंने केएलएफ का गठन किया। उन्होंने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएसएफ) के प्रेसिडियम गुट के सशस्त्र विंग के रूप में केएलएफ के बैनर तले माई भागो रेजिमेंट का गठन किया। केएलएफ जो 1994 तक सक्रिय रहा, भारत में आतंकवाद विरोधी अभियान में काफी कमजोर पड़ने के बाद, 1995 तक इसके कैडर की ताकत 23 होने का अनुमान था। 2009 में इंटर– सर्विसेज–इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा मलेशिया में केएलएफ को पुनर्जीवित किया गया। केएलएफ नेतृत्व वर्तमान में यह मानता है कि वे पराजित खालिस्तान आंदोलन को आतंकवादी हमले करके जो समाज को सांप्रदायिक आधार पर स्वीकृत कर पुनर्जीवित कर सकते हैं।12

3.खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) रू खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का गठन 1993 में रणजीत सिंह नामक एक छोटे–मोटे अपराधी ने किया था, जो तस्करी में शामिल था और जम्मू के सिंबल कैंप का निवासी था। उसने आरएस पुरा और सांबा इलाकों में सीमा पार के तस्करों के साथ संपर्क बनाने और जम्मू क्षेत्र के सिख युवकों को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद KZFका गठन किया। रणजीत सिंह को 1993 में महाराष्ट्र में गिरफतार किया गया था। हालांकि, वह दिसंबर 1995 में पुलिस हिरासत से भाग गया और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। वर्तमान में ड्रैथ का संस्थापक लाहौर में रहता है और सीमा पार से हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है।

1982 में प्रतिबंध के समय, इसके सदस्यों की संख्या 560 थी। इसके लगभग 80 प्रतिशत कार्यकर्ता 20–30 आयु वर्ग के थे, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से थे और उनमें से 60 प्रतिशत गैर– स्नातक और अविवाहित थे, जो राज्य भर के गुरुद्वारों में रहते थे। अपने शुरुआती दिनों में दल खालसा की पांच सदस्यीय सर्वोच्च परिषद थी जिसमें हरसिमरन सिंह मुख्य आयोजक (मुख पंच) थे। अन्य सदस्य गुरदासपुर के जसवंत सिंह और पांवटा साहिब के सतनाम सिंह, हरभजन सिंह नारेंगवाल और गजिंदर सिंह (एक पूर्व सरकारी कर्मचारी) थे जो 1981 के इंडियन एयरलाइंस अपहरण में शामिल थे। वर्तमान में दल खालसा के महासचिव परमजीत सिंह टांडा हैं, जबकि हरपाल सिंह चीमा अध्यक्ष, बाबा हरदीप सिंह मेहराज उपाध्यक्ष और कंवर पाल सिंह प्रवक्ता हैं।13

निष्कर्ष एवं सुझाव– भारत सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किया जाना चाहिए–

– भारत और विदेशों में सिखों को कट्टरपंथ से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

– सभी संबंधित दलों को राष्ट्रीय मुद्दों को राजनीति से अलग रखना होगा।

– खालिस्तान जैसे बड़े मुद्दे पर भारत सरकार और पंजाब सरकार को एक साथ मिलकर काम करना होगा और मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना होगा।

– किसी भी तरह की क्रिया को राजनीतिक आम सहमति पर आधारित होना चाहिए कोई भी एक तरफा कार्रवाई करने से बचना होगा।

– यदि हम इस तरह के प्रयास को राजनीति की वजह से कमजोर होने देते हैं तो हम पंजाब में सिर्फ एक नया अलगाववादी फ्रैंकस्टीन पैदा कर रहे होंगे।

– केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर यह आम सहमति बननी चाहिए कि यदि खाली स्थान समर्थक संगठन फिर से उठ खड़े होते हैं तो उन सभी दलों की अपनी राजनीतिक

प्रासंगिकता काम हो जाएगी।

– इसके साथ ही साथ केंद्र एवं पंजाब सरकार को एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम को छोड़कर पंजाब में कानून एवं व्यवस्था पर जोर देना चाहिए हालांकि किसी भी कार्यवाही को करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कार्यवाही सिख जनता सिख धर्म पर कार्यवाही के रूप में ना देखें इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है इससे हमें सीख लेनी होगी।

– इसके अलावा विदेशों में खालिस्तान सक्रियता को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।

– इसके लिए भारत सरकार को उन देशों से बातचीत करनी चाहिए जहां खालिस्तान आंदोलन सक्रिय है भारत सरकार को उन देशों में आंदोलन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

– इसके अलावा विदेशों में खालिस्तान तत्वों से निपटने के लिए एक सरल उपाय अभी हो सकता है कि भारत में सिखों की स्थिति क्या है इसे लेकर विदेशी मीडिया सांसदों एवं जनता से समझदारी से बातचीत की जाए और इस तरह के नकारात्मक प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जाए।

– इसके साथ ही भारत सरकार को खालिस्तान गतिविधियों से जुड़े लोगों के बारे में भारत में रह रहे सिखों के बीच सच्चे आंकड़ों को पेश किया जाए जिससे वह सही वह गलत का फर्क कर सके ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पुंज, बलवीर, दैनिक जागरण संपादकीय, 1 अप्रैल 2014, राष्ट्रीय संस्करण
2. सिद्धू, जी.बी.एस.(2014), खालिस्तान षडयंत्र की इनसाइड स्टोरी(हिंदी अनुवाद) प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 84,
3. Milewski, Terry(2021) Blood for Blood, Fifty years of the Global Khalistan Project , Harper Collins Publishers, India, peg no 107
4. www.loksabhadocs.nic.in
5. Singh, Jagtar(2011) Rivers on fire, first edition, Aakar Books, peg no 63,
6. www.indicode.nic.in
7. www.satp.org
8. www.britannica.com
9. www.nytimes.com
10. http//www.satp.org
11. ibid
12. ibid
13. ibid
14. ibid.